Title: Regarding return of investment from the Sahara Group of Companies.-laid

डॉ. सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट): सहारा इंडिया कंपनी ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की अपनी दो कथित फर्जी संस्थाओं के द्वारा 3.07 करोड़ गरीब लोगों से 25 हजार करोड़ रुपये एकत्र करके वित्तीय अनिममितताएँ की हैं । यद्यपि अंतिम राहत के लिए मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है । 5 करोड़ से ज्यादा लोग सहारा इंडिया से अपने निवेश की वापसी न होने से हताश और निराश हैं, देश के कई हिस्सों से इनके आत्म हत्या और खुदखुशी के समाचार मिलते रहते हैं । सहारा इंडिया उपरोक्त विषय में संतोषजनक व्यवहार नहीं कर रही हैं । जब भी सरकार के मंत्रालय ने उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करती है, ये लोग कथित रूप से तुरंत दूसरे मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में नयी कंपनी बनाकर पूरे पैसे को उसमे डाल देते हैं । लोग सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप न होने से निराश हैं । लोगों को अपनी गाढ़ी कमाई की वापसी के बारे में पता नहीं है, जो कई वर्षों से सहारा इंडिया की कई संस्थाओं/योजनाओं में बस जमा ही है परन्तु उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है । मैं सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि इसे गंभीरता से लें और सभी सम्बद्ध मंत्रालयों की एक टीम बनाकर कार्य करें । सरकार को निश्चित समय सीमा के भीतर सहारा से रिफंड के संबंध में जनता को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए अन्यथा सहारा इंडिया घोटाले की संसद और टीवी चैनलों में केवल चर्चा ही होती रहेगी जिससे जनता का भला नहीं होने वाला । प्रभावित लोगों सबसे अधिक गरीब लोग हैं । मेरा सरकार से निवेदन हैं कि सरकार इस दिशा में शीघ्र आवश्यक कदम उठाए ।